Losses suffered by FCI

1615. SHRI VIRENDRA KATARIA : Will the Minister of FOOD be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 2132 given in the Rajya Sabha on the 17th December, 1993 and state :

(a) the losses suffered by the Food Corporation of India during the last three years, year-wise as a result of damage done; and

(b) the precautionary steps taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI) : (a) The details of losses suffered by the Food Corporation of India duting the last three years as a result of damage due to theft are as under :—

Year	Amount (In lakhs)
	Rs.
1990-91	15.00
1991-92	23.38
1992-93	8.15

(b) Keeping in view the storage capacity and the prevailing local conditions, Food Corporation of India Watch and Ward staff, State Armed Police and Central Industrial Security Force are deployed to guard the Corporation's godowns.

Regular checks on outgoing and incoming vehicles are done to tally stocks with gate passes. A procedure for locking, sealing and opening of the godowns has been laid down. Services of local law enforcing agencies are also being utilised as and when required. For vulnerable depots, police patrolling is arranged Physical verification of stocks and surprise inspections of godowns are conducted on regular basis.

चीनी उत्पादक एसोसिएशनों को गन्ना-विकास के लिए दिया जाने वाला ऋण

1616. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**

श्रीराम जेठमलानी :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार चीनी उत्पादक संस्थाओं को गन्ना-विकास के लिए आसान शर्तों पर ऋण और अनुदान प्रदान करती है ।

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, 1993 तक गन्ना विकास योजनाओं के लिए दी गई धनराशि का इकाई-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त ऋण को लौटाने के लिए कितनी समावधि और उस पर ब्याज की कितनी दर निर्धारित की गई है;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान गन्ना विकास योजनाओं के अंतर्गत दिए गए ऋणों का भुगतान नियमित रूप से होता रहा है;

(ङ) यदि हां, तो दिसम्बर, 1993 तक दिए गए ऋणों की कितनी राशि का भुगतान ऋण की शर्तों के अनुसार कर दिया गया है और उस देय राशि का ब्यौरा क्या है जिसका भुगतान नहीं किया गया है;

(च) क्या यह भी सच है कि विकास योजनाओं पर धन खर्च करने के बावजूद 1990-91 की तुलना में 1992-93 में प्रति हेक्टेयर गन्ने की औसत उपज कम थी; और

(छ) यदि हां, तो 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के वर्षों के दौरान प्रति हेक्टेयर औसत उपज कितनी-कितनी थी ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) चीनी उपक्रमों को (और न कि चीनी उत्पादक एसोसिएशनों को) अपने कार्यचालन के क्षेत्रों में गन्ने का विकास करने के लिए चीनी विकास निधि से ऋण दिए जाते हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) चीनी उपक्रमों को दिए जा रहे ऋण पर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की रियायती दर पर ब्याज लगाया जाता है । इस ऋण की वापसी